

an>

Title: Need to enhance the payment of Aanganwadi Sewaks and Sahayaks.

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर) : 24 लाख आंगनबाड़ी सेवक तथा आंगनबाड़ी सहायक देश के ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र में गत 42 वर्षों से अपनी सेवाएँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संलग्न एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत अर्पित कर रहे हैं। इन आंगनबाड़ी सेवक/सहायक वर्ग में काम करने वाले सभी ने मिलकर अपनी मांगों, जैसे कि उनको मिलने वाले मानधन को बेसिक-पे में बदल कर जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिलना चाहिए तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल छुट्टी व पेड छुट्टी एवं पेंशन जैसी सुविधाएँ तथा 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पूरक आहार खर्च, ड्यूटी ड्रेस कोड मेटेरियल खर्च, आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए मिलने वाला प्रासंगिकता खर्च, ऐसे सभी खर्च में बढ़ोतरी मिलने के बारे में कई बार सरकार के सामने प्रस्ताव रखे और प्रदर्शन भी किए हैं जिससे वह अपनी निजी लाइफ में आने वाली समस्या और बढ़ती हुई महंगाई के बारे में न सोचते हुए उन्हें सौंपी गई सेवाएँ सेवाभाव से और प्रभावी तरीके से अर्पित कर सकें। आज देश में हम डिजिटलाइजेशन की तरफ अपनी नींव को मजबूत बना रहे हैं। इस दौर में आंगनबाड़ी सेवक तथा आंगनबाड़ी सहायक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी को कंप्यूटर ट्रेनिंग तथा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराने की भी जरूरत है।

इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध तथा निवेदन करती हूँ कि इन आंगनबाड़ी सेवक तथा आंगनबाड़ी सहायकों की मांगों को सरकार जल्द से जल्द स्वीकार करें, ताकि यह लोग अपनी सेवाएँ पूरे योगदान से अर्पित करें और वह अपना रिपोर्टिंग आसानी से व तुरंत अपने अधिकारी वर्ग को करने के लिए इन सबको लैपटॉप इश्यू किए जाएँ।

यह मांग सरकार से करती हूँ जिसके चलते देश अतिशीघ्र ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र को लेकर डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े।